राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक : 07.12. 2018
स्थान –नया प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के 65 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत्त
Minutes of the 65th Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 65वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन दिनांक 07.12. 2018 को नया सभागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची में किया गया।

बैठक का आरम्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के उप महाप्रबंधक श्री विन्सेंट लकड़ा द्वारा सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत संबोधन से हुआ | श्री लकड़ा ने अपने संबोधन में "ग्राम स्वराज अभियान" के द्वितीय चरण के दौरान एवं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने पर सभी संबंधित बैंको एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया | उन्होंने वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे MSME Support & Outreach programme के अंतर्गत राज्य में चिन्हित सभी चार जिलों बोकारो, गोड्डा, खूंटी एवं जमशेदपुर के LDMs एवं वहां मौजूद बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की | उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम छमाही के दौरान बैंको द्वारा ACP में दिए गये लक्ष्यों के विरुद्ध लगभग 50% उपलब्धि के लिए बैंको को बधाई दी और जिन क्षेत्रों में बैंको का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा है, उन क्षेत्रों में उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की | कृषि के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार के लिए एवं NPA ऋण की वसूली के लिए उन्होंने बैंको एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया | अंत में उन्होंने पिछली SLBC की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत SLBC द्वारा उठाये गए क़दमों की जानकारी देते हुए राज्य के विकास में SLBC की सक्रिय भागीदारी का आश्वाशन दिया |

तत्पश्चात मंच पर आसीन झारखण्ड सरकार के विकास आयुक्त श्री डी. के. तिवारी; भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक एवं OIC श्री संजीव दयाल; नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री शरद झा एवं बैंक ऑफ़ इंडिया के वित्तीय समावेशन विभाग,प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक श्री शंकर प्रसाद का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया |

बैठक में उपरोक्त सम्मानित अतिथियों के अलावे झारखण्ड सरकार के अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी; झारखण्ड राज्य स्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख; झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक एवं विभिन्न बैंकों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे ।

स्वागत कार्यक्रम के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक एवं OIC श्री संजीव दयाल को बैठक को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया । अपने सम्बोधन मे श्री दयाल ने SLBC के agenda book में उतरोत्तर किये जा रहे बदलावों/सुधारों/अतिरिक्त जानकारियाँ सम्मिलित किये जाने पर SLBC की पूरी team की प्रशंसा की | उन्होंने कृषि क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर चिंता व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया कि agr sub-committee की बैठक कर सभी हितधारकों (NABARD, Govt एवं बैंको)

State Level Banker Committee BOI Jharkhand

को मिलकर bankable projects बनाने की जरुरत है जो बैंकों एवं borrowers दोनों के लिए लाभप्रद हो | उन्होंने राज्य में NPA loans और खासकर सरकार प्रायोजित योजनाओं में अधिक NPA होने की स्थिति की गंभीरता पर सभा का ध्यान आकृष्ट किया | उन्होंने SLBC को प्रत्येक quarter की समाप्ति के 25 दिनों के अन्दर सभी जिलों को आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जिससे DCC/DLRC की बैठकों में जिला स्तर पर प्रस्तुत किये जानेवाले आंकड़ों में विसंगतियां न रहें | साथ ही उन्होंने प्रत्येक तिमाही के दौरान बैंको के incremental deposit और incremental advances के आधार पर हुए CD ratio की जानकारी देने का सुझाव दिया | Karnataka Bank, Indian Bank एवं Allahabad Bank द्वारा किये गए रिपोर्टिंग की खामियों पर उन्होंने अप्रसन्नता जाहिर की और SLBC को निर्देश दिया कि इन बैंको से इस सम्बन्ध में explanation माँगा जाये | Agr sub committee में हुए discussion के आधार पर उन्होंने SLBC द्वारा बैंको के सहयोग से राज्य में small & marginal farmers से सम्बंधित आंकड़ों को उपलब्ध करने के लिए एक format devise किये जाने का सुझाव दिया | उन्होंने LDMs से ACP बनाते वक़्त यह ध्यान रखने को कहा कि बैंको को target PLP के आधार पर न देकर पिछले वर्ष में हुई उपलब्धि के आधार पर target दिए जाएँ | इसके साथ ही उन्होंने नाबार्ड से यह सुनिश्चित करने को कहा कि DDMs द्वारा DCC की बैठक में PLP समय पर उपलब्ध कराया जाये | उन्होंने NABARD से यह भी आग्रह किया कि झारखण्ड ग्रामीण बैंक एवं State Cooperative Bank के साथ इस बात पर परिचर्चा करें कि उनके यहाँ बैंक में कार्यरत स्टाफ ही FLC के रूप में कार्य कर रहें हैं जो RBI के दिशा निर्देशों के अनूरूप सही नहीं है | उन्होंने रांची , गुमला एवं पाकुर जिलों में FLC के कार्यरत नहीं होने की जानकारी देते हुए सभी जिलों के Lead Banks से उनके जिलों में FLC की नियुक्ति को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया | इसके साथ ही उन्होंने SLBC द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सभी FLC एवं उसके परिचालन के लिए अधिकृत अधिकारियों (Phone Nos.& E-mail Addresses) की जानकारी दिए जाने का निर्देश दिया |

अगले वक्ता के रूप में NABARD के मुख्य महाप्रबंधक श्री शरद झा ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित Agr Food Summit की जानकारी देते हुए सभा को बताया कि इस summit के दौरान लिए गए कुछ निर्णयों ;जैसे-झारखण्ड में high tech agr को बढ़ावा देना, राज्य को organic hub के रूप में विकसित किया जाना, water harvesting की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना , इजरायल द्वारा झारखण्ड में centre of excellence की व्यवस्था किया जाना और पतंजलि ग्रुप द्वारा mega food park को अधिगृहित किया जाना; से राज्य में कृषि के क्षेत्र में सुदुरगामी परिणाम दिखाई देंगे | NABARD द्वारा राज्य में कृषि के क्षेत्र में उठाये गए कतिपय क़दमों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि RIDF के तहत रु 1500 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध रु 1340 करोड़ का disbursement कर दिया गया है और लगभग 21000 SHGs के digitization का कार्य पूर्ण कर लिया गया है | उन्होंने कई schemes, जैसे- water shed एवं FPO के अंतर्गत दिए गए grant एवं किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी सभा को दी | Agr Sub Committee की बैठक में हुए परिचर्चा के आधार पर उन्होंने agr sector में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु बैंको एवं राज्य सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्य करने की आवश्यकता बताई:

- KCC के coverage को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा पंचायतवार किसानों की जानकारी बैंक को दिया जाना
- कृषि के क्षेत्र में long term loans को प्राथमिकता देकर capital formation किया जाना
- तसर एवं लाह के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया जाना
- प्रत्येक जिले में कृषि के क्षेत्र में Ground Level Credit को बढ़ाने के लिए NABARD द्वारा प्रस्तावित format के अनुसार LDMs, DDMs एवं DAOs के द्वारा संयुक्त रूप से survey किया जाना
- आन्ध्र प्रदेश की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा tenant farmers के लिए loan eligibility certificates जरी किया जाना
- डेयरी को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा Jharkhand Milk Federation के साथ tri-partite agreement किया जाना, एवं

State Level Banker Committee BOI Jharkhand

- NABARD द्वारा milk production को बढाने के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट तैयार करना

इसके पश्चात BOI, FI Deptt, HO के महाप्रबंधक श्री शंकर प्रसाद ने अपने संबोधन में सभी हितधारकों को Financial Inclusion के क्षेत्र एवं GSA के दौरान दोनों चरणों में सराहनीय कार्य करने के लिए बधाई दी | उन्होंने वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे MSME outreach programme की जानकारी देते हुए सभी हितधारकों से इस प्रोग्राम को सफल बनाने की अपील की और राज्य में MSME sector में प्रथम छमाही के दौरान ACP के विरुद्ध 52% की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया | इसके साथ ही उन्होंने राज्य में agr sector में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में कृषि योग्य भूमि का न बढाया जा सकना, कम उत्पादन, उन्नत कृषि तकनीकों की कमी, low water retention capacity of land आदि factors के कारण कृषि क्षेत्रमे अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है | उन्होंने इसके विकल्प के तौर पर organic farming को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया | उन्होंने राज्य में medicinal plants और vegetables के उत्पादन पर विशेष जोर दिए जाने को कहा | उन्होंने KVK जैसे संस्थाओं की मदद से किसानों के skill development किये जाने, animal husbandry activities के तहत dairy, goatery, piggery एवं fishery के लिए लोन दिए जाने और rain water harvesting system, check dams, drip irrigation system इत्यादि को मजबूत बनाये जाने की बात कही | इसके साथ ही उन्होंने agr colleges और universities में best education practices अपनाये जाने की बात कही |

इसके बाद बैंक ऑफ़ इंडिया , रातू शाखा में BC के रूप में कार्यरत जागृति महिला समूह (SHG) की सखी दीदी श्रीमती पुष्पा देवी ने अपने अनुभवो को साझा किया | इसके साथ ही बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिकारी श्री विभव कुमार ने SHG की महिलाओं को BC के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया और उनसे होने वाले फायदे की जानकारी सभा को दी | JSLPS और बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा इस विषय पर बनायीं गयी एक लघु चित्र को भी सभा में दर्शाया गया ताकि अन्य बैंक भी इस दिशा में आगे आयें |

विकास आयुक्त श्री डी. के. तिवारी ने अपने संबोधन के प्रारंभ में SLBC के रिपोर्ट को पिछली रिपोर्ट से बेहतर बताते हुए SLBC एवं सभी बैंको को वित्तीय समावेशन, विशेषतः ग्राम स्वराज अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बधाई दी | उन्होंने पिछली तिमाही की तुलना में CD ratio में हुई मामूली वृद्धि को सकारात्मक कदम बताया और बैंको से और अधिक प्रयास कर राष्ट्रीय मानक तक पहुँचने की अपील की | उन्होंने सभा को यह जानकारी दी कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति पर चल रही एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी में भाग लेने के कारण राज्य के मुख्य सचिव, वित्त सचिव, कृषि सचिव और अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारियों की SLBC की बैठक में उपस्थिति नहीं हो पाई | उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री के 2022 तक किसानों के आय को दोगुना किये जाने के मिशन में बैंको से सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से किये गए Global Agr Food Summit की जानकारी दी | उन्होंने बताया कि इस summit के दौरान राज्य सरकार द्वारा खास कर agriculture और farmers पर ज्यादा focus दिया गया जिसमे राज्य के सुदूरवर्ती भागों से आये किसानों को नयी तकनीक और नए–नए उपकरणों की जानकारी दी गयी | उन्होंने कई किसानों से summit के दौरान उनसे हुए interaction की बुनियाद पर उनके प्रगतिशील और प्रतिभावान होने की बात कही और बैंको से आग्रह किया कि उन्हें उनकी जरूरतों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाये | उन्होंने बैंको को सलाह दी कि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढाने हेतु ऐसे प्रगतिशील किसानों को चिन्हित कर उन्हें MUDRA योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयता दी जाये जो खेती के साथ साथ अन्य allied activities जैसे dairy, poultry, fishery इत्यादि sector में भी कार्य कर रहे हैं | उन्होंने SLBC को अगली बार से बैंको के overall performance एवं incremental performance दोनों के आधार पर ranking किये जाने का निर्देश दिया | साथ ही उन्होंने दो अच्छे कार्य करने वाले बैंको को पारितोषिक अथवा प्रशस्ति पत्र दिए जाने और असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले बैंको को caution दिए जाने का निर्देश दिया | उन्होंने राज्य में सुखाड़

State Level Banker Committee BOI Jharkhand

जैसी प्राकृतिक आपदा के मद्देनज़र बैंको से आने वाले समय में किसानो के साथ नरमी से पेश आने और RBI के नियमों के तहत घोषित सुविधाओं को दिए जाने की बात कही | SLBC से उन्होंने यह विशेष रूप से कहा कि लंबित मुद्दों के समाधान के लिए SLBC की त्रैमासिक बैठकों का इंतज़ार न करें और बीच–बीच में उनकी सहमति लेकर उनके कार्यलय कक्ष में सभी सम्बंधित हितधारकों के साथ बैठक की जाये ताकि इन मुद्दों के निराकरण में तेजी लायी जा सके | उन्होंने BC के रूप में नियुक्त किये गए सखी मंडल की महिला द्वारा सभा में अनुभव साझा करने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और साथ ही सभी बैंको से यह आग्रह भी किया कि राज्य में कार्यरत BC की संख्या के अलोक में इनकी कम संख्या को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सखी मंडल की महिलाओं को BC के रूप में नियुक्त किया जाये | उन्होंने MSME सेक्टर में बैंको के अच्छे प्रदर्शन को बरक़रार रखने की हिदायत दी |

व्यवसाय सत्र (Business Session): मुख्य प्रबंधक, SLBC, श्री दीप शंकर द्वारा व्यवसाय सत्र की कार्यवाही शुरू करते हुए सबसे पहले दिनांक 10.08.2018 को आयोजित 64वी एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत की संपुष्टि सभा द्वारा करायी गयी |

राज्य सरकार से संबंधित मामले:

SLBC द्वारा राज्य सरकार से उनसे सम्बंधित दो मामलों, land records को update किये जाने और dedicated recovery certificate officer की नियुक्ति किये जाने के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किये जाने का आग्रह किया गया |

बैंक से संबधित मामले :

तत्पश्चात श्री दीप शंकर ने एसएलबीसी की 64वीं बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं पर बैंक से प्राप्त Action Taken रिपोर्ट को क्रमवार प्रस्तुत किया, जिसपर किये गए discussion और आगे की जानेवाली अपेक्षित कार्यवाही का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है:

क्रम सं.	कार्यवाही बिंदु	कार्यवाही के लिए अपेक्षित मुद्दे	कार्यवाही के लिए चिन्हित विभाग
1	Incremental CD ratio	RBI द्वारा SLBC से राज्य में प्रत्येक तिमाही के अंत में deposit और advances में हुए growth के आधार पर Bankwise/Districtwise incremental CD ratio की जानकारी दिए जाने का निर्देश दिया गया	SLBC
2	Small Finance Bank	राज्य में कार्यरत small finance banks के लिए SLBC द्वारा target निर्धारित किये जाने का निर्देश दिया गया	SLBC
3	Achievement of ACP in Agr Advances	Agr Advances में substantial growth के लिए agr sub committee की हुई बैठक में परिचर्चा के अनुसार investment credit और agr value chain financing को बढाने के लिए agr infrastructure को सुदृढ़ करने हेतु policy frame किया जाना	NABARD/Govt. Deptt/SLBC/RBI

4	Correct एवं Timely data का submission	सभी बैंको से SLBC को correct एवं timely data दिए जाने का निर्देश दिया गया	SLBC द्वारा सभी बैंको से यह आग्रह किया गया कि समय सीमा की पाबंदी के कारण बैंको को data sumission/correction के लिए बहुत अधिक समय नहीं दिया जा सकता , अतः हबैंक अपने स्तर से पूर्णतः जांचोपरांत correct डाटा ही submit करें		सभी बैंक
5	DFS द्वारा identified सभी uncovered centres पर BC की नियुक्ति तथा पलामू में चिन्हित सभी centres पर brick & mortar branch का खोला जाना	बैंको से राज्य में identified सभी locations पर निर्धारित समयावधि के अंदर बैंक की शाखाएं खोलने तथा BC नियुक्त किये जाने का आग्रह किया गया	पलामू में SBI द्वारा 2 एवं यूनियन बैंक द्वारा 1 शाखा खोला जाना है	VGB द्वारा दुमका , लातेहार एवं गढ़वा के 10 केन्द्रों पर BC की नियुक्ति की जानी है	BC की नियुक्ति में SHG की महिलाओं को preference दिया जाना		SBI, Union Bank of India एवं VGB
6	बैंको के performance के आधार पर ranking किया जाना	विकास आयुक्त के निर्देशानुसार अगली SLBC की बैठक से बैंको के overall performance एवं incremental performance दोनों के आधार पर ranking किया जाना	साथ ही दो अच्छे कार्य करने वाले बैंको को पारितोषिक अथवा प्रशस्ति पत्र और असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले बैंको को caution दिए जाने का प्रावधान		SLBC / सभी बैंक
7	CD Ratio	40% से कम CD ratio वाले बैंको/जिलों में Monitorable Action Plan के आधार पर किये जाने वाली कार्यवाहियों से सरकार को अवगत कराना			सम्बंधित बैंक/LDMs
8	पंचायत भवन मुख्यालयों में ATM की व्यवस्था	IG, operations के कार्यालय के द्वारा प्रदत्त 140 centres के list को SLBC द्वारा सभी LDMs को उपलब्ध कराकर उनसे वैसे सभी centres को visit कर यह बताने को कहा गया था कि यदि उन locations के पास कोई बैंक की शाखा अथवा ATM नहीं है तो वहां बैंको को चिन्हित कर उनका नाम SLBC को प्रेषित किया जाये ताकि उन जगहों पर चिन्हित बैंको को एटीएम खोलने के लिए कहा जा सके	अब तक केवल तीन LDMs-जामतारा, खूंटी एवं गुमला , के द्वारा यह exercise किया गया है	चूँकि कई बैंको ने ATM लगाये जाने पर अपनी सहमति दी है अतः बाकि LDMs से आग्रह किया गया कि इस exercise को वे अबिलम्ब पूरा करें		LDMs (जामतारा, खूंटी एवं गुमला को छोड़कर)

9	PMFBY	State Co-operative Bank एवं झारखण्ड ग्रामीण बैंक से PMFBY के तहत covered किये गए किसानों के डाटा को पोर्टल पर upload किये जाने के लिए कहा गया।	State Co-operative Bank एवं झारखण्ड ग्रामीण बैंक
10	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	सभी बैंको से PMMY के तहत दिए गए नए ऋण का अलग से और साथ ही साथ ऋण प्राप्त लाभार्थियों द्वारा generate किये गए employees की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा गया	सभी बैंक
11	PMAY	सभी बैंको से आग्रह किया गया कि वे अपने यहाँ sanction किये गए वैसे housing loans के cases को जो PMAY scheme के अंतर्गत स्वीकृति की पात्रता रखते हैं, उन्हें PMAY scheme में convert करें और subsidy की राशी का claim सम्बंधित विभाग से करें।	सभी बैंक/ शहरी विकास एवं आवास विभाग
12	किसी भी विषय की गंभीरता और जरुरत के अनुसार इससे सम्बंधित उपसमिति की बैठक कराना	विकास आयुक्त महोदय ने SLBC की बैठक का इंतज़ार न करके विषय के importance के अनुसार कभी भी उनकी सहमति लेकर इससे सम्बंधित उपसमिति की बैठक कराये जाने का निर्देश दिया।	SLBC एवं उपसमितियों के convener सदस्य
13	DCC/DLRC meeting	पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, दुमका, गढ़वा और पलामू के LDMs से Sep quarter का DCC/DLRC meeting अविलम्ब कराये जाने का अनुरोध किया गया।	संबंधित LDMs

विकास आयुक्त ने बैंक से सम्बंधित मामलों के चर्चा के उपरांत सभा को बताया कि revenue deptt के द्वारा land records के digitization का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने सभी बैंको से यह आग्रह किया कि dedicated certificate officer के office establishment के खर्च में बड़ी राशि की आवश्यकता को देखते हुए बैंको द्वारा एक बार पुनः इस पर विचार किया जाना चाहिए।

सभी बैंको के महत्वपूर्ण संकेतक

इस विषय पर सभा को बताया गया कि Y-o-Y basis पर की जाने वाली तुलना के साथ साथ SLBC द्वारा राज्य में पिछले तिमाही की तुलना में हुई वृद्धि/ह्रास की जानकारी भी देने का प्रयास किया गया है और अगली बैठक से इसकी रिपोर्टिंग में और भी आवश्यक संशोधन करने का प्रयास किया जायेगा। महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदायों को दिये जाने वाले ऋण से संबंधित रिपोर्टिंग में कई बैंको द्वारा काफी variation किये जाने की तरफ सभा का ध्यान आकृष्ट कराया गया और सभी से इस पर ध्यान देने की अपील की गई। SLBC द्वारा RBI के observation पर बैंको की संख्या में लगभग प्रत्येक quarter में हो रहे बदलाव की जानकारी bankwise/districtwise देने का आश्वाशन दिया गया।

(Action: SLBC, सभी बैंक)

वार्षिक ऋण योजना के आधार पर वर्ष 2018-19 की उपलब्धि की समीक्षा

इस विषय पर मुख्य प्रबन्धक श्री दीप शंकर ने जानकारी देते हुए बतलाया कि reporting quarter के दौरान बैंको ने ACP target के विरुद्ध लगभग 50 % achievement कर लिया है। सभा को बताया गया

कि पिछले quarter के दौरान राज्य में बैंको द्वारा दर्ज की गयी incremental CD ratio 51.51% है | कई sectors में बैंको द्वारा reporting में की गयी खामियों की चर्चा की गयी और उनसे आने वाले समय में reporting में आवश्यक सुधार किये जाने का आग्रह किया गया | सभा को बैंक की शाखाओं की संख्या के आधार पर की गयी रैंकिंग की जानकारी दी गयी | **(Action: सभी बैंक एवं SLBC)**

कृषि ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड

इस पर चर्चा करते हुए सभा को बताया गया कि कृषि क्षेत्र में वर्तमान तिमाही में रु 1018 करोड़ के संवितरण एवं KCC में रु 743 करोड़ संवितरण के बावजूद कुल o/s में क्रमशः रु 213 करोड़ की वृद्धि एवं रु (-) 2 करोड़ की ह्रास दर्ज की गयी है, जिससे reporting की accuracy पर संदेह होता है |

(Action: बैंक)

MSME ऋण

CGTMSE से covered रु 2 करोड़ तक के eligible MSME ऋण खातों की कम संख्या पर SLBC द्वारा RBI को बताया गया कि अगले वित्तीय वर्ष से पोर्टल में आवश्यक सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बैंको को CGTMSE से covered खातों की संख्या के साथ साथ उन खातों की जानकारी भी देनी पड़ेगी जहाँ extant guidelines का उल्लंघन कर third party guarantee और/अथवा collateral security ली जा रही है | **(Action: सभी बैंक एवं SLBC)**

MSME पर होनेवाली परिचर्चा के दौरान RBI के उप महाप्रबंधक श्री राजेश तिवारी ने सभा में यह बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में झारखण्ड के चार जिलों में चलाये जा रहे MSME outreach programme के मद्देनज़र MSME sector को और अधिक गति प्रदान करने के लिए RBI द्वारा 25-26 दिसम्बर तक राज्य के किसी भी चयनित जिले में कैंप आयोजित किया जायेगा जहाँ MSME sector के prospective borrowers को बैंको से credit linkage कराने का प्रयास किया जायेगा | इसके लिए उन्होंने LDMs से स्वतः आगे आने की अपील की | SLBC की मीटिंग के बाद जिलों में DCC/DLRC की बैठक कराये जाने के SLBC के आग्रह पर उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से जिलों में इन बैठकों का आयोजन प्रत्येक तिमाही के अंत के 25 दिनों के बाद कराये जाने का प्रावधान किया जायेगा ताकि SLBC द्वारा इन जिलों से सम्बंधित आंकड़े LDMs को उपलब्ध कराया जा सके | उन्होंने यह जानकारी दी कि RBI द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगले quarter से जिलों में DCC की बैठक के दौरान RBI के officials मौजूद रहेंगे और साथ ही उसी visit के दौरान उनके द्वारा FLC/BC locations और Branch visit भी किया जायेगा और सभी LDMs को LDOs की सहायता से इसके अनुसार सभी सम्बंधित विभागों से समन्वय करने का निर्देश दिया | **(Action: सभी LDMs एवं सभी LDOs)**

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

सभा को बताया गया कि सभी बैंको के द्वारा PMMY के तहत DFS द्वारा दिए गए बजट को district wise allocate कर SLBC को प्रेषित कर दिया गया है | परन्तु पिछली SLBC कि बैठक के दौरान वित्तीय सेवाएँ विभाग के संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा द्वारा मुद्रा योजना के तहत दिए गए नए ऋण का अलग से और साथ ही साथ ऋण प्राप्त लाभार्थियों द्वारा generate किये गए employees की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध कराने को जो निर्देश दिया गया था उसमे किसी भी बैंक द्वारा ये आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया है | **(Action: SLBC एवं सभी बैंक)**

सभा में नगर विकास विभाग के सहायक निदेशक, श्री संजय कुमार ने PMAY के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति न होने पर बैंको से विशेष drive चलाकर इसमें प्रगति लाने का आग्रह किया | उन्होंने बैंको को दिए गए 16000 संभावित borrowers की लिस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस लिस्ट में शामिल लोगों को contact कर इस दिशा में अपेक्षित प्रगति लायी जा सकती है | उन्होंने NHB के प्रतिनिधियों से भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की बात कही | इसके जबाब में SLBC द्वारा उनसे आग्रह किया गया कि ULB के सदस्यों एवं बैंको के संयुक्त प्रयास से इन borrowers को contact कर पाना उचित होगा |

(Action: शहरी विकास विभाग एवं सभी बैंक)

State Level Banker Committee BOI Jharkhand

एसएचजी महिलाओं के वित्त पोषण हेतु योजना

दिनांक 20.11.2018 को SLBC की SHG पर गठित sub committee की बैठक में JSLPS के CEO श्री परितोष उपाध्याय द्वारा दिए गए निर्देश के अलोक में सभी बैंको से यह आग्रह किया गया कि वे SHG ऋण के स्वीकृति /वितरण के लिए camp लगाकर त्वरित गति से काम करें | BOI के महाप्रबंधक श्री शंकर प्रसाद ने बैंको से SHG को स्वीकृत की गयी राशि को वितरित किये जाने का आग्रह किया | उन्होंने यह भी कहा कि स्वीकृत की गयी राशि को पूर्णतया utilize कराये जाने अथवा disburse किये जाने से कृषि ऋण में भी प्रयाप्त वृद्धि हो सकती है क्योंकि ज्यादातर SHG कृषि क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं | SLBC द्वारा JSLPS के प्रतिनिधियों से यह आग्रह किया गया कि सभी बैंको को दिए गए टारगेट के विरुद्ध rational आधार पर आवेदन प्रेषित किये जाएँ | **(Action: सभी बैंक एवं JSLPS)**

वित्तीय समावेशन/प्रधानमंत्री जन धन योजना

SLBC द्वारा सभा को बताया गया कि झारखण्ड में अभी भी RuPay कार्ड के activation का कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है और प्रतिदीन 50 से कम transaction करने वाले BC की संख्या काफी अधिक है अर्थात कई BC का कार्य संतोषजनक नहीं है, जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है | कई जगहों पर कई बैंको के द्वारा BC की नियुक्ति में आ रही परेशानी को देखते हुए SLBC द्वारा SSAs के alottment का fresh exercise किये जाने की आवश्यकता बताई गयी | BOI के महाप्रबंधक श्री शंकर प्रसाद ने बैंको द्वारा अपने ही BC के साथ सही व्यवहार नहीं किये जाने एवं उनके bill को सही समय पर नहीं pay किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया और सभी नियंत्रक प्रमुखों से इस पर उचित कार्यवाही करने का आग्रह किया | **(Action:SLBC,सभी संबंधित बैंक एवं LDMs)**

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य सरकार से लंबित पड़े certificate cases एवं SARFAESI cases के त्वरित निष्पादन का आग्रह किया गया | SLBC के उप महाप्रबंधक श्री विन्सेंट लकड़ा द्वारा सभी बैंको से यह आग्रह किया गया कि विभिन्न जिलों में SARFAESI के अंतर्गत physical possession के लिए जिलाधिकारियों के पास पड़े लंबित cases की जानकारी पूर्ण विवरण के साथ SLBC को उपलब्ध करायी जाये जिसे राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीयों के साथ share किया जा सके | **(Action: राज्य सरकार एवं बैंक)**

PMEGP/PMAY/NULM

SLBC द्वारा सभी बैंको से इन schemes के तहत लंबित आवेदनों के अतिशीघ्र निष्पादन का आग्रह किया गया | SLBC के उप महाप्रबंधक श्री विन्सेंट लकड़ा द्वारा सभी बैंको से यह आग्रह किया गया कि वर्तमान में चल रहे MSME outreach progaramme के तहत PMEGP आवेदनों की स्वीकृति से सम्बंधित आंकड़ों की भी DFS द्वारा monitoring की जा रही , अतः इसपर विशेष focus देते हुए इसका त्वरित निष्पादन किया जाये, जिससे subsidy claim करने के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके | उन्होंने NHB के प्रतिनिधि से PMAY के अंतर्गत पात्रता रखने वाले borrowers के पूर्व में स्वीकृत housing loans को इस scheme में benefit दिलाने के लिए बैंको के साथ समन्वय करने की सलाह दी |

(Action: सभी बैंक एवं MSME outreach programme के तहत चिन्हित चार जिलों के LDMs)

RSETI एवं FLCC

रामगढ में PNB के द्वारा RSETI के भवन निर्माण में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण RSETI की sub committee की बैठक में हुए निर्णय के अलोक में PNB की जगह अन्य बैंक को यह जिम्मेदारी दिये जाने की चर्चा के क्रम में BOI के महाप्रबंधक श्री शंकर प्रसाद ने यह कहा कि RSETI भवन के निर्माण की जिम्मेदारी extant guidelines के अनुसार सम्बंधित जिले में जो अग्रणी बैंक है, उनको दी जानी चाहिए | चूँकि रामगढ में BOI अग्रणी बैंक है, अतः यह जिम्मेदारी BOI को दी जा सकती है | इसपर SLBC द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत RSETI से सम्बंधित प्रतिनिधि को इसपर निर्णय लेने के लिए special meeting कराने का आग्रह किया गया | **(Action: SLBC एवं राज्य सरकार)**

State Level Banker Committee BOI Jharkhand

विविध कार्यसूची

1. IOB से Mudra Promotion Campaign में हुए खर्च की राशी के लिए रु 77400 contribute किये जाने का आग्रह किया गया , जिसपर CRM, IOB श्री मोती लाल ने जल्द ही कार्यवाही किये जाने का आश्वाशन दिया | **(Action: IOB)**

2. Urban Development & Housing Finance, GoJ के पत्रांक 2295 दिनांक 24.09.2018 के द्वारा DAY-NULM scheme के SEP Component के लिए तैयार किये गए centralised bank code और product code को सभी बैंको द्वारा अपने database में आवश्यक updation किया जाना था , जिसमे केवल BOI, SBI एवं Union Bank के द्वारा ही कार्य किया गया है | शेष सभी बैंको से इस पर अविलम्ब कार्य करने को कहा गया | सम्बंधित विभाग की अधिकारी के अनुरोध पर SLBC द्वारा इससे सम्बंधित communication सभी नियंत्रक प्रमुखों को पुनः दिए जाने का आश्वाशन दिया गया और नियंत्रक प्रमुखों से यह आग्रह किया गया कि वे अपने शाखाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दें | सभी बैंको से आग्रह किया गया कि इसकी अद्यतन सूचना से Urban Development & Housing Finance, GoJ को अवगत करा दें | **(Action: सभी सम्बंधित बैंक)**

3. DFS द्वारा identified 440 centres पर BC की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान VGB के द्वारा वैसे 11 centres जिनपर या तो connectivity issue अथवा किसी अन्य बैंक का SSA होने के कारण BC नियुक्त नहीं किया गया है , पर BC नियुक्त किये जाने की बात कही गयी | VGB के साथ साथ जामतारा, गढ़वा एवं लातेहार के LDMs से आग्रह किया गया कि यदि उन स्थानों पर कोई अन्य बैंक के BC कार्यरत हैं तो इसकी जानकारी SLBC को दी जाये | **(Action: VGB एवं LDMs- जामतारा, गढ़वा एवं लातेहार)**

4. सभी LDMs से आग्रह किया गया कि राज्य के सभी 4178 SSA को पुनः नए सिरे से बैंको को allot किये जाने की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में SLBC द्वारा जल्द ही दिए जाने वाले निर्देश के तहत उनसे इसपर कार्यवाही करने के लिए तैयार रहने को कहा गया | **(Action: सभी LDMs)**

5. SBI एवं Union Bank द्वारा पलामू में शेष 03 स्थानों Untari Road, Ramgarh एवं Pandu में शाखा खोलने के लिए कहा गया | **(Action: SBI एवं Union Bank of India)**

6. MSME outreach programme के तहत राज्य में चिन्हित चार जिलों में प्रत्येक शुक्रवार को mega camp किये जाने की जानकारी दी गयी और सभी बैंक से यह आग्रह किया गया कि इन जिलों में LDM द्वारा दिए गए schedule के अनुसार कैंप का आयोजन करें | **(Action: SLBC एवं सभी बैंक)**

7. सभी नियंत्रक प्रमुखों से अपनी शाखाओं को निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया कि JSLPS के निर्णय के अलोक में प्रत्येक माह में एक दिन Community Based Recovery Mechanism की meeting की जाये जिसके लिए माह के दुसरे सप्ताह में बुधवार का दिन निर्धारित किया गया है | **(Action: सभी सम्बंधित बैंक)**

8. रांची जिले के साथ साथ सभी जिलों के LDMs से डिजिटल transaction को बढ़ावा दिए जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा merchants को onboard किये जाने का आग्रह किया गया | **(Action: सभी LDMs)**

State Level Bankers Committee * Jharkhand *

BOI के महाप्रबंधक श्री शंकर प्रसाद ने, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम जिसके तहत प्रत्येक व्यस्क नागरिकों का बैंक खाता खोला जाना और उन्हें social security schemes जैसे PMJJBY एवं PMSBY से cover किया जाना शामिल है , पर सभी बैंको से विशेष ध्यान देने की अपील की | उन्होंने इस कार्य के लिए बैंको को मिलने वाले कमीशन की जानकारी भी सभा को दी |

अंत में Union Bank of India के DGM श्री बिपन सिंह द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा के समाप्ति की घोषणा की गयी |

(विन्सेंट लकड़ा)
उप महाप्रबंधक, रा.स्त.बै.स.